सं. 1(2)/2025-समन्वय
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

जुलाई, 2025 माह के लिए डीपीई का मासिक सारांश

1.. सीपीएसई का संचालन: -

i. लोक उद्यम विभाग ने 16 जुलाई, 2025 को ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) में बोर्ड स्तर से नीचे के 13 पदों को तत्काल आमेलन के नियम से छूट देने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति भेज दी।

ii. डीपीई ने दिनांक 09.07.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों का अनुसरण करने वाले सीपीएसई के लिए महंगाई भत्ते को संशोधित किया है।

iii. डीपीई ने दिनांक 22.07.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई की सतर्कता नीति पर समेकित एवं संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

2. समझौता ज्ञापन- सीपीएसई का कार्य निष्पादन मूल्यांकन:

वर्ष 2024-25 के लिए : समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 90 सीपीएसई के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन लेखापरीक्षित लेखाओं के उपलब्ध होने के पश्चात अक्टूबर, 2025 में आरंभ होगा।

वर्ष 2025-26 के लिए : वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में, 87 सीपीएसई (87 में से) के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

3. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल नोट्स: -

(i) जुलाई, 2025 माह मे 02 सीएमसीडीसी बैठकों में भाग लिया गया।

(ii) जुलाई, 2025 माह मे 03 अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठकों में भाग लिया गया।

(iii) जुलाई, 2025 माह में 02 मध्य-वर्ष समीक्षा बैठकों में भाग लिया गया।

4. क्षमता निर्माण: -

(i) डीपीई ने एसजेवीएन लिमिटेड के सहयोग से 10 और 11 जुलाई, 2025 को धर्मशाला में सीपीएसई के पूर्णकालिक निदेशकों (एफडी) के क्षमता निर्माण के लिए आवासीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न सीपीएसई के 22 पूर्णकालिक निदेशकों (एफडी) ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें निदेशक-मंडल की प्रभावकारिता और पूर्णकालिक निदेशकों की भूमिका, बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों के लिए कार्यनीतिक प्रबंधन, परिवर्तनकारी बोर्ड नेतृत्व, सीपीएसई में लेखापरीक्षा कार्य की प्रभावकारिता में सुधार और महत्वपूर्ण डीपीई दिशानिर्देशों से संबंधित सत्र प्रतिष्ठित संकाय द्वारा लिए गए।
(ii) डीपीई के 89 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने जुलाई, 2025 तक आई-गॉट (I-GOT) पोर्टल पर 3416 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

(iii) डीपीई के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में, डीपीई के 3 अधिकारियों ने एनएचपीसी लिमिटेड का दौरा किया तथा डीपीई के 5 अधिकारियों ने सीपीएसई की कार्यप्रणाली से परिचित होने के लिए जीआरएसई लिमिटेड का दौरा किया।

5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

डीपीई और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से 31 जुलाई, 2025 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों पर केंद्रित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर पाँचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उपर्युक्त राज्यों के आकांक्षी जिलों (एडी) के 100 से अधिक प्रतिभागियों सहित सभी

हितधारकों, सीपीएसई के सीएसआर नोडल अधिकारियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों, नीति आयोग, कार्यान्वयनकारी एजेंसियों, डीपीई और यूनिसेफ के अधिकारियों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

6. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएँ

(i) डीपीई ने 18 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में सीपीएसई के लिए उद्योग 4.0 पर दो कार्यशालाएँ आयोजित कीं, जिनमें सीपीएसई के वरिष्ठ कार्यपालकों (सीएमडी और निदेशकों) और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशालाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तनकारी उत्पादकता, दक्षता और नवाचार हेतु उभरती उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। सचिव (डीपीई) और विशेषज्ञों ने एआई, डिजिटल ट्विन, 3डी प्रिंटिंग आदि जैसी प्रौद्योगिकियों तथा उद्योगों में परिवर्तन लाने में इन प्रौद्योगिकियों की भूमिका और सीपीएसई के लिए भावी राह पर विस्तृत चर्चा की।

(ii) जुलाई, 2025 माह में सीपीएसई/एसएलपीई के अधिकारियों के लिए डीपीई द्वारा 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई।

7. मिशन भर्ती

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 12 जुलाई, 2025 को आयोजित रोजगार मेले के 19वें चरण में सीपीएसई के 3,766 नए नियुक्त व्यक्तियों को शामिल किया गया। डीओपीटी द्वारा आयोजित रोजगार मेले के 16 चरणों में अब तक सीपीएसई के 62,166 नए नियुक्त व्यक्तियों को शामिल किया जा चुका है।

8. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति: -

एएमआरसीडी डैशबोर्ड से 31.07.2025 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पोर्टल पर 217 मामले दर्ज किए गए हैं। वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर 51 मामले अस्वीकृत कर दिए गए। 51 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 94 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समिति के पास हैं। शेष 21 मामले संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास उनकी जाँच और अनुमोदन हेतु लंबित हैं।

*****